[श्री काशी नाथ पाण्डेय]

ग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो बंगाल के लोग हैं, वह यू० पी० में जा कर काम करते हैं, बिहार के लोग असम में जा कर काम करते हैं, पंजाब के लोग यू० पी० में जा कर काम करते हैं, मद्रास में जा कर काम करते हैं। अगर आप ने यह आवाज उठाई कि फलां जगह के मजदूर वहीं रहें, तो यह हिन्दुस्तान को डिस्इंटेग्रेट करना होगा। इस तरह से हिन्दुस्तान की सालिडैरिटी कायम नहीं रह सकती है। मैं लेबर मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि बार बार इस चीज को इन्वाइट करना ठीक नहीं है। वह इस चीज को मौका ही न दें, इस को बन्द करें। इस पर काफी बहस हो चुकी है।

17.29 hrs

[Mr. Speaker *in the Chair*]

आज पब्लिक सेक्टर में क्यों इतनी औद्योगिक अशान्ति है, इस के रूट काज पर आप को जाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि एम्प्लायमेंट की जिम्मेदारी बहुत सी मिनिस्ट्रीज की है। लेकिन जब एम्प्लायमेंट के सम्बन्ध में कोई चर्चा होती है तब लेबर मिनिस्ट्री उस के लिये जिम्मेदार ठहराई जाती है। जब किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट में आदमियों को रक्खा जाता है तो सब से बड़ी कुरीति यह है कि पहले तो वह आदमियों को भर लेते हैं, फिर उस के बाद मैन-पावर असेसमेंट कमेटी जो सेंटर की है वह असेस करती है कि इतने आदमी लेने चाहियें, और जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाती है, तब उस प्रोजेक्ट के चार-पांच हजार आदमी सरप्लेस घोषित कर दिये जाते हैं। उस के बाद प्राबलैम आप खुद क्रियेट करें कंट्री के लिए तो यह ठीक नहीं है। तब यह एक चिन्ता का विषय बन जाता है। यह उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि लेबर मिनिस्ट्री इसको भी देखे।

मौलिक तौर पर औद्योगिक शान्ति आज इस बात पर निर्भर करती है कि लेबर मैटर्ज से कौन डील करता है। पब्लिक सैक्टर में जो परसौनल आफिसर रखा जाता है उस को रखते वक्त लेबर मिनिस्ट्री से कोई राय नहीं ली जाती है। कोई फौज का रिटायर्ड आदमी होता है तो कोई दूसरा सिविलियन आफिसर होता है और उसको उठा कर परसौनल आफिसर बना दिया जाता है। जिस ने अपने तमाम जीवन में ह्यूमन मैटर्ज से कभी डील नहीं किया उसको पच्चीस हजार या दस हजार मजदूरों से डील करने का काम सौंप दिया जाता है। इस तरह से कैसे आप आशा कर सकते हैं कि औद्योगिक शान्ति बनी रहे। मैं चाहता हूं कि लेबर मिनिस्ट्री इस चीज को सीरियसली टेक अप करे और देखे कि पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज में जो परसौनल डिपार्टमैंट हैं, उनको ठीक किया जाए और जो नियुक्ति है, वह लेबर मिनिस्ट्री की राय से हो।

17.31 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : Sir, as decided by the Business Advisory Committee to-day just now under your Chairmanship, the Debate on the Demands for Grants of the Ministry of Labour and Rehabilitation will conclude to-day and the Labour Minister may be asked to reply at 6.30 p. m.

AN HON. MEMBER : It was 4 hours.

MR. SPEAKER : Not only this Ministry, some other Departments, also like Social Welfare Department, they want to discuss. They want three hours. So, if you do not cut one or two hours somewhere, we will not reach those Ministries at all and they will be guillotined.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : Was anything decided about our dinner to-day ?

MR. SPEAKER : Therefore, we cut one hour from Labour, one hour from Works and Housing. They agreed that Social Welfare would have 3 hours on the last day, that this, day after tomorrow.

I would only appeal to the hon. Members just to take five minutes each and at 6.30 the hon. Minister will reply and by 7 we will finish so that we may take 2 or 3 more Ministries before we finish day after tomorrow.

17.33 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS
1968-69—*Contd.*

Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation—*Contd.*

MR. SPEAKER : Hon. Members may now move the cut motions to Demands for Grants relating to the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, subject to their being otherwise admissible.

All the hon. Members who want to speak will get a chance. I do not want to deny that to anybody.

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि "श्रम नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें ।

[गुप्त मतदान द्वारा मजदूरों के प्रतिनिधियों की यूनियन को मान्यता देने में असफलता जिसके कारण कारखानों में राष्ट्रीय मजदूर संघ को थोपा गया (4)]

कि "विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें

[विस्थापित व्यक्तियों को समुचित नौकरी और काम देने में विफलता (15)]

कि "विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें

[दतिया नगर, मध्य प्रदेश के बेघरबार हुए दुकानदारों को दुकान के लिए जमीन देने की व्यवस्था करने में विफलता (16)]

कि "श्रम नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय" शीर्षक के अन्तर्गत 100 रुपये कम कर दिये जायें

[दोषपूर्ण श्रम नीति को बनाये रखना जिससे कारखानों में उत्पादन के लिये शान्तिपूर्ण वातावरण नहीं बन पाता (17)]

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): I beg to move :

That the demand under the head Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation be reduced by Rs. 100.

[Failure to improve the miserable lot of the workers engaged on the construction of roads. (18)]

That the demand under the head Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation be reduced by Rs. 100.

[Failure to improve the lot of labourers engaged on Mangalore Port Project (19)]

That the demand under the head Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation be reduced by Rs. 100.

[Failure to improve the lot of labourers engaged on Tuticorin Port Project (20)]

That the demand under the head Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation be reduced by Rs. 100.

[Failure to increase the facilities of port workers (99)]

That the demand under the head Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation be reduced by Rs. 100.

[Failure to accede to the demands of dock workers (100)]

That the demand under the head Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation be reduced by Rs. 100.

[Need to step up the welfare works for dock workers (101)]

SHRI KIRUTTINAN (Sivaganga) : I beg to move :

That the demand under the head Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation be reduced by Rs. 100.

[Failure to rehabilitate the Burma repatriates fully (126)]